''भारत का विकास एजेंडा सतत विकास लक्ष्यों में परिलक्षित होता है'' - लोक सभा अध्यक्ष

जयपुर, 20 अगस्त, 2016: आज जयपुर में राजस्थान विधान सभा कक्ष में ब्रिक्स महिला सांसद मंच की पहली बैठक का उद्घाटन करते हुए लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि भारत का विकास एजेंडा सतत विकास लक्ष्यों में परिलक्षित होता है। उन्होंने समावेशन और सामाजिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में की गई कुछ पहलों अर्थात् जन धन योजना/वित्तीय समावेशन संबंधी राष्ट्रीय मिशन, बेटी बचाओ/बेटी पढ़ाओ अथवा बालिकाओं को प्रोत्साहित और उनको शिक्षित बनाने संबंधी योजना, मेक-इन इंडिया, कौशल विकास, डिजिटल इंडिया आदि का उल्लेख किया।

यह उल्लेख करते हुए कि ब्रिक्स एक नया समूह है, श्रीमती महाजन ने कहा कि विश्व की 43 प्रतिशत जनसंख्या ब्रिक्स देशों में रहती है और इनका विश्व सकल घरेलू उत्पाद में 37 प्रतिशत योगदान है। इस प्रकार, सतत विकास लक्ष्यों की सफलता पूरी तरह से ब्रिक्स देशों में उसके सफल कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि ब्रिक्स ने आपसी हितों के आर्थिक मुद्दों पर परामर्श हेतु एक मंच से शुरूआत करके स्वयं को एक ऐसे समूह के रूप में विकसित किया है, जिसके एजेंडा में इस समय विभिन्न विश्व स्तर के सामयिक मुद्दे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत के नेतृत्व के दौरान ब्रिक्स सहयोग और अधिक मजबूत होगा।

श्रीमती महाजन ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायकों के रूप में महिला सांसदों की भूमिका को जन प्रतिनिधि के रूप में जनता से जुड़े सरोकारों पर जोर देने तथा शासन और सतत विकास संबंधी मुद्दों पर नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने में सहायता करने में उनकी भूमिका पर केन्द्रित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि 2030 एजेंडा, नीति संबंधी पहलों के विभिन्न चरणों पर जवाबदेही और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में राष्ट्रीय सांसदों द्वारा अदा की जाने वाली अनिवार्य भूमिका को भी मान्यता प्रदान करता है।

इससे पूर्व, राजस्थान की इस बैठक के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे को बधाई देते हुए श्रीमती महाजन ने कहा कि बैठक के विषय पर चर्चा करने के लिए राजस्थान से बेहतर स्थान नहीं हो सकता था। श्रीमती महाजन ने सतत विकास के क्षेत्र में राजस्थान की उत्कृष्ट परंपरा का उल्लेख किया। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है और वह भी केवल तीन-चार महीनों में ही होती है। यहॉ के लोगों ने जल संरक्षण और जल संसाधनों के सतत उपयोग की एक सुदृढ़ परंपरा विकसित की है। उन्होंने इस बात की सराहना की कि

वर्ष 1997-2007 के दौरान नौ सूखों के बावजूद राजस्थान के लापोड़िया गॉव में एक भी जल टैंकर की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि गॉव में एक अनूठी बांध प्रणाली विकसित की गई जिसे ''चौका'' कहा जाता है। महिलाओं द्वारा प्रेरित पहला पर्यावरण आंदोलन चिपको आंदोलन (महिलाएं पेड़ से लिपटकर उन्हें बचाती थीं) था। जो राजस्थान राज्य में 18वीं शताब्दी में प्रारम्भ हुआ था।

अपने स्वागत भाषण में राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष श्री कैलाश मेघवाल ने इस बात पर बल दिया कि आने वाले वर्षों में हमें इन विकास लक्ष्यों को प्राप्त करके गरीबी और भूख की समस्या को जड़ से मिटाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता और स्वच्छता, महिला पुरुष समानता तथा सभी के लिए गरिमापूर्ण जीवनयापन सुनिश्चित करना होगा। श्री मेघवाल ने कहा कि ब्रिक्स देशों की महिला सांसदों की भूमिका सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति करने में बहुत सहायक होगी। उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए महिला सांसद कानून बनाते समय विचार-विमर्शों में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी। इसके अलावा महिला सांसद इन कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए विधायिका की विभिन्न समितियों में पर्याप्त दबाव बना सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का सामाजिक परीक्षण, विभिन्न परियोजनाओं की जांच में एक अत्यधिक प्रभावी उपकरण सिद्ध हुआ है और आशा व्यक्त की कि महिला सांसद सामाजिक परीक्षण की इस महत्वपूर्ण भूमिका को प्रभावपूर्ण ढंग से निभाने में समर्थ होंगी।

उपस्थितजनों को सम्बोधित करते हुए दक्षिण अफ्रीका के शिष्टमंडल की प्रमुख सुश्री तांडी आर. मोडीसे, चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविन्सिस ने कहा कि महिला सांसदों की यह जिम्मेदारी है कि वे 17 सतत विकास लक्ष्य तथा उनके 169 लक्ष्य क्षेत्रों की प्राप्ति करने में अपनी सरकारों की मंशाओं, प्रयासों और हासिल की गई प्रगति का जायजा लें। उन्होंने यह बात स्वीकार की कि सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। उन्होंने महसूस किया कि महिलाओं का अभी भी राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा/शासन, वित्त, व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद सदस्यों को परिवर्तन के चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करना होगा, जिसमें ऐसे निर्णय लेने की प्रक्रिया भी शामिल है जो लिंग भेद पर ध्यान न देते हुए समस्त दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है।

राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से उद्घाटन सत्र की शोभा बढ़ाई। लोकसभा उपाध्यक्ष डॉक्टरएम थंबीदुरई; ब्राजील से शिष्टमंडल की प्रमुख प्रोफेसर दोरीना सेअबरा रेजेन्डे, एमपी (डीईएम/टीओ); रूस से शिष्टमंडल की प्रमुख सुश्री गलिना कारेलोवा, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ फेडरेशन; चीन से शिष्टमंडल की प्रमुख सुश्री वन मा, मेम्बर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ दी नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना, चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल एंड ज्यूडिशियल अफेयर्स कमेटी ऑफ दी नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना; दक्षिण अफ्रीका से शिष्टमंडल की प्रमुख सुश्री तांडी आर. मोडीसे, चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोविन्सिस; भारत सहित ब्रिक्स देशों के अन्य प्रतिनिधियों तथा अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने समारोह में भाग लिया।

तत्पश्चात बैठक में पूर्णकालिक सत्र में "संधारणीय विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन संबंधी परिप्रेक्ष्य" विषय पर विचार-विमर्श हुआ। रूसी फेडरेशन परिषद की उपाध्यक्ष सुश्री गेलिना करोलोवा ने सत्र की अध्यक्षता की और श्रीमती के.कविता, संसद सदस्य लोक सभा संचालक थी।

श्रीमती कविता के. ने सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वनय में विकासशील देशों के समक्ष आ रही चुनौतियों को रेखांकित किया। उन्होंने "ब्रिक्स" देशों की स्थिति तथा सतत विकास लक्ष्यों मुद्दों पर व्यापक तंत्र का निर्माण करने में महिला सांसदों की भूमिका को भी उजागर किया। प्रो. डोरिनहा सीब्रारेजेन्डे, संसद सदस्य तथा ब्राजील की प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने कहा कि ऊर्जा सक्षमता के लिए पारस्परिक सहयोग पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए और महिलाओं को वैश्विक रूप से संधारणीय समाज के निर्माण के लिए नेता के रूप में उपाय करने हेतु महिला भागीदार बनाने पर जोर दिया जाना है। चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति की सदस्य सुश्री वेन मां ने सामूहिक प्रयास की अपील की जिससे इन लक्ष्यों की प्राप्ति में अधिक बल मिलेगा साथ ही उन्होंने कहा कि चीन वैश्विक सहयोग के लिए ब्रिक्स के अन्य देशों के साथ काम करने के लिए तैयार है। सुश्री एन. मार्चेसी, दक्षिण अफ्रीका की सांसद ने इस बात पर बल दिया कि वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्षमता निर्माण और प्रोद्योगिकी एवं ज्ञान का अर्जन महत्तवपूर्ण है। कुमारी शैलजा, राज्य सभा संसद सदस्य ने संधारणीय विकास लक्ष्य की प्राप्ति में वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण के महत्व पर बल दिया।

अपराह्न में "सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति - नागरिकों को शामिल करते हुए महिला सांसदों की भूमिका" विषय पर बैठक का पहला सत्र आयोजित किया गया। सत्र की अध्यक्षता सुश्री वेन मां और श्रीमती सुप्रिया सूले, संसद सदस्य लोक सभा ने की। श्रीमती गीता के., संसद सदस्य ने सत्र का संचालन किया। सत्र का शुभारंभ करते हुए सुश्री वेन मां ने टिप्पणी की कि

विकास राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और लोगों की खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए यह सभी देशों का साझा दायित्व है। उन्होंने आगे कहा कि लोक केंद्रित दृष्टिकोण के सिद्धांत को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा संधारणीय विकास में सभी व्यष्टियों की सहभागिता को सुकर बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करना महत्वपूर्ण है।

प्रो. ड्रोरिनहा सीब्रा रिजेंडे, संसद सदस्य ब्राजील ने कहा कि महिला सांसदों को सभी जगह सकारात्मक परिवर्तन लाने तथा सभी व्यक्तियों की समानता, नागरिकता और खुशहाली के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। सुश्री सालिया मुर्जबैवा, संसद सदस्य, स्टेट ड्यूमा कमिटी आन हेल्थ रूस ने कहा कि महिला सांसद अपने प्रयासों के समेकित करके नए वैश्विक विकास लक्ष्यों के संवर्धन और कार्यान्वयन में लोक मत के निर्माण में एक बड़ा योगदान दे सकती हैं। ब्राजील की संसद सदस्य सुश्री जियोवानिया डे सा, ने चर्चा में भाग लेते हुए यह राय व्यक्त की कि अर्थव्यवस्थाओं के समेकन के माध्यम से महिलाओं को काम-काज और सम्मान प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर से ऊपर उठने की आवश्यकता है। ब्राजील की सुश्री लेंड्रेन ने कहा कि महिलाओं को राजनीतिक असमानता कम करने और महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने के लिए उन्हें अधिकाधिक संख्या में राजनीति में आना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका की सुश्री टी. वाना, संसद सदस्य ने जनता की सुनवाई के लिए संसद को लोगों तक पहुंचाने के एक अद्वितीय कार्यक्रम का हवाला दिया। ब्राजील की सुश्री डामिना पेरेरा, संसद सदस्य ने कहा कि संसदीय विकास लक्ष्यों को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। श्रीमती जया बच्चन ने कहा कि विकास की कार्यनीतियों का ध्यान महिला समानता, मूलभूत स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा में निवेश और गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित होना चाहिए।

श्रीमती संतोष अहलावत, संसद सदस्य; लोक सभा, श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर, संसद सदस्य; लोक सभा श्रीमती आर. वनरोजा, संसद सदस्य; कुमारी शोभा कारांदजाले, संसद सदस्य, लोक सभा; श्रीमती झराना दास वैद्य, संसद सदस्य, राज्य सभा; और सुश्री दर्शना विक्रम जरदोश, संसद सदस्य, लोक सभा ने भी चर्चा में भाग लिया।